



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 19, 2014/माघ 30, 1935
No. 42] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 2014/MAGHA 30, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2014

(सनसेट समीक्षा)

विषय: चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाईलैंड तथा श्रीलंका में उत्पादित या निर्यातित प्लेन मीडियम डेन्सिटी फाइबर बोर्ड के आयात पर लगाये गये प्रतिपाटन शुल्क की सनसेट समीक्षा ।

सं.15/28/2013-डीजीएडी.- समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां पर अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पहचान डंप की गई मर्चें की पहचान, मूल्यांकन और शुल्क का संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे यहां पर एडी नियमावली के रूप में संदर्भित किया गया है) को ध्यान में रखते हुए पदनामित प्राधिकारी (जिसे प्राधिकारी के रूप में संदर्भित किया गया है) ने चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में उत्पादित अथवा निर्यातित प्लेन मीडियम डेन्सिटी फाइबर बोर्ड (जिसे यहां पर विषयगत वस्तुओं के रूप में संदर्भित किया गया है) के आयात के संबंध में मूल प्रतिपाटन जांच पड़ताल शुरू की थी तथा दिनांक 26 अगस्त, 2009 की अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं. 14/12/2007-डीजीएडी के अंतर्गत निश्चित प्रतिपाटन शुल्क की सिफारिश की गई थी। तदनुसार वित्त मंत्रालय की दिनांक 8 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना सं. 116/2009-सीमाशुल्क के अंतर्गत चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाईलैंड तथा श्रीलंका (जिसे यहां विषयगत देशों के रूप में संदर्भित किया गया है) में उत्पादित या निर्यातित विषयगत वस्तु के सभी प्रकार के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया था ।

समीक्षा का अनुरोध

2. जबकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1995 के अनुसार लगाये गये प्रतिपाटन शुल्क को जब तक वापस न ले लिया जाए, इस प्रकार प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने की तारीख के पांच वर्ष पश्चात् लागू नहीं रहेगा।

3. और, उपर्युक्त प्रावधान की प्रवाह न करते हुए, प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से इस प्रकार के उपाय के समाप्त की तारीख से तर्कसंगत अवधि पहले पर्याप्त अनुरोध के आधार पर इस बात की समीक्षा की जा सकती है कि क्या इस शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने और पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

4. और जबकि उपर्युक्त प्रावधानों की शर्तों के अनुसार ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मंगलम टिम्बर प्रोडक्ट्स लिमिटेड जोकि भारत में प्लेन मीडियम डेनसीटी फाइबर बोर्ड के मुख्य निर्माता है, ने वित्त मंत्रालय की दिनांक 8 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना सं. 116/2009-सीमाशुल्क के अंतर्गत विषयगत देशों में उत्पादित अथवा निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर पहले लगाये गये प्रतिपाटन शुल्क की सेनसेट समीक्षा का अनुरोध करते हुए यथावत कारणों वाले आवेदन के साथ प्राधिकारी को लिखा है और इन विषयगत देशों में उत्पादित अथवा निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क के जारी रखे जानी की मांग की है। यह अनुरोध इस आधार पर आधारित है कि इन विषयगत देशों में उत्पादित अथवा निर्यातित विषयगत वस्तुओं का पाटन इन विषयगत देशों से इन विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने के बावजूद जारी रहा है तथा विषयगत देशों से पाटन होने के कारण घरेलू उद्योग को लगातार क्षति हो रही है। आवेदक ने यह भी दलील दी है कि विषयगत देशों के विरुद्ध उपाय की समाप्ति से पाटन होना जारी रहेगा तथा इसकी पुनरावृत्ति होगी तथा घरेलू उद्योग को भी क्षति पहुंचेगी।

5. तथा, प्राधिकारी, आवेदकों द्वारा दिये गये प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर इस बात पर विचार करता है कि लागू प्रतिपाटन शुल्क की सेनसेट समीक्षा की कार्रवाई शुरू करना विषयगत देशों से आफ सेट पाटन की तरफ इस प्रकार के शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की जांच पड़ताल जारी रखने के लिए समुचित होगा तथा इस प्रकार की जांच पड़ताल करने के लिए समुचित होगा कि क्या कि यदि शुल्क को हटा लिया जाता है अथवा अलग-अलग दरों में रखा जाता है तो क्या घरेलू उद्योग को इससे क्षति होते रहने अथवा इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

घरेलू उद्योग और स्टैंडिंग

6. यह आवेदन ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मंगलम टिम्बर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जिसे यहां घरेलू उद्योग अथवा आवेदक के रूप में संदर्भित किया गया है) जोकि प्लेन मीडियम डेनसीटी फाइबर बोर्ड के मुख्य उत्पादक है, द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने अन्य कंपनियों को सूचीबद्ध किया है जिनकी प्लेन मीडियम डेनसीटी फाइबर बोर्ड बनाने की क्षमता है अर्थात् रसील डैक्कर लिमिटेड, शिरडि इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बाला जी एक्शन बिलबेल और न्यूकेम लिमिटेड और यह भी कहा है कि न्यूकेम लिमिटेड तथा एक और कंपनी, बजाज इको-टेक प्रोडक्ट्स लिमिटेड अब संबंधित उत्पाद का उत्पादन नहीं कर रहा है। रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, आवेदकों का न केवल कुल घरेलू उत्पादन पर एक बहुत बड़ा हिस्सा है जोकि घरेलू उद्योग का हिस्सा है अपितु यह नियमों के प्रयोजन के भीतर मौजूदा सेनसेट समीक्षा के आवेदन को दायर करने की स्टैंडिंग की अपेक्षा को भी पूरा करते हैं।

जांच शुरूआत

7. समीक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए घरेलू उद्योगों द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक प्रथम दृष्टया के आधार पर संतुष्ट होने पर प्राधिकारी, लागू शुल्क को बनाये रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए और इस बात की समीक्षा करने के लिए कि क्या इन शुल्कों के समाप्त किये जाने से पाटन और क्षति बनी रहेगी अथवा इसकी पुनरावृत्ति होगी, प्रतिपाटन नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार एतद्वारा सेनसेट समीक्षा प्रारंभ करता है।

विचारार्थ उत्पाद और मिलती जुलती मर्दे

8. मौजूदा समीक्षा जांच में विचारार्थ उत्पाद है प्लेन मीडियम डेनसीटी फाइबर बोर्ड जिसकी मोटाई 6 मिलीमीटर अथवा इससे अधिक हो (जिसे यहां पर विचारार्थ उत्पाद के रूप में संदर्भित किया गया है।)

9. विषयगत वस्तुओं के संबंध में पिछली समीक्षा जांच में प्राधिकारी ने विचारार्थ उत्पाद और इसके दायरे को निम्नानुसार परिभाषित किया है:-

"6. विचारार्थ उत्पाद है प्लेन मीडियम डेनसीटी फाइबर बोर्ड जिसे बाजार की भाषा में प्लेन एमडीएफ बोर्ड कहते हैं। प्लेन मीडियम डेनसीटी फाइबर बोर्ड अथवा प्लेन एमडीएफ बोर्ड लकड़ी का एक संयोजित उत्पाद है जो लकड़ी के अवशिष्ट रेशों को यूरिया फोरमेलडीहाइट रेजिन अथवा मेलामाइन रेजिन के साथ आपस में जोड़ कर उष्मा और दबाव डाला जाता है। इसके समतल और एक समान फिनिश के कारण इसका पार्टिशन, मोडूलर फर्नीचर, कैबनेट इत्यादि में प्रयोग किया जाता है एफडीएफ बोर्ड प्लेन रूप में उत्पादित किया जाता है। तथा इसके ऊपर बाद में प्रोसिंग करते लेमिनेशन की जाती है जोकि प्लेन एफडीएफ बोर्ड के उत्पादन के पश्चात् की जाती है। लेमिनेटिड मीडियम डेनसीटी फाइबर बोर्ड विचारार्थ उत्पाद के दायरे में नहीं आता है। प्राधिकारी ने विचारार्थ उत्पाद के संबंध में प्राप्त पत्रों पर अपनी प्रारंभिक जांच में विचार किया और समुचित जांच पड़ताल के पश्चात् 6 मिलीमीटर से कम मोटाई वाले प्लेन मीडियम डेनसीटी फाइबर बोर्ड को उत्पाद के दायरे से हटा दिया और तदनुसार विचारार्थ उत्पाद को 6 मिली मीटर अथवा इससे अधिक मोटाई वाले प्लेन मीडियम डेनसीटी फाइबर बोर्ड के रूप में विचार किया गया तथा इसी पर ही इस जांच पड़ताल में विचार किया जाता है।

7. इस उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 44.11 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतक है तथा यह मौजूदा जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं है"।

10. जांच में विचारार्थ उत्पाद का दायरा वही होगा जो पहले अधिसूचित अंतिम निष्कर्ष में विचारार्थ उत्पाद का है।

11. इसके अलावा आवेदक ने उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद और तथा विषयगत देशों से भारत में आयात की गई विषयगत वस्तुएं मिलती जुलती मर्दे हैं तथा अभिप्राय प्रतिपाटन नियमावली के दायरे में है; यह कि विषयगत देशों से आयात की गई विषयगत वस्तुओं तथा इसका घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है; यह कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित विषयगत

वस्तुएं तथा विषयगत देशों से आयात किये गये वस्तुएं आवश्यक उत्पाद विपेशताओं जैसे कि भौतिक और रसायनिक गुणों, उत्पादन प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्दिष्टता, कीमत, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की शर्तों के अनुसार तुलनीय है; यह कि उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं में आपस में आदान-प्रदान करके प्रयोग कर सकता है और कर रहा है और यह कि दोनों का तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे के स्थान में प्रयोग किया जा सकता है ।

प्रक्रिया

12. इस जांच से यह निर्धारण होगा कि क्या इन उपायों के समाप्त होने से पाटन और क्षति होना जारी रहेगा अथवा उनकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। प्राधिकारी इस आशय की जांच पड़ताल करेगा कि क्या ड्यूटी के लगाये रखने को जारी रखना आफसेट पाटन के लिए आवश्यक है और क्या यदि ड्यूटी को हटा दिया जाता है अथवा इसमें परिवर्तन किया जाता है तो क्या इसे क्षति जारी रहेगी अथवा उनकी पुनरावृत्ति होगी।

- i. यह समीक्षा, दिनांक 8 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना सं. 116/2009-सीमा शुल्क के सभी पहलुओं को अपने दायरे में शामिल करेगी।
- ii. इस समीक्षा जांच में शामिल देश है- चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका
- iii. मौजूदा समीक्षा के आशय से जांच की अवधि है- अक्टूबर, 2012 से सितम्बर, 2013 तथा क्षति विश्लेषण के लिए पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2010-11, 2011-12, 2012-13 के आंकड़ों तथा पीओआई पर विचार किया जाएगा।
- iv. नियमावली के नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

13. सम्बद्ध देश के निर्यातकों भारत स्थित उनके राजदूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में ज्ञात प्रयोक्ताओं और आयातकों तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित स्वरूप और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सम्बोधित किया जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं **संबद्ध** शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
कमरा नं. **240**, उद्योग भवन
नई दिल्ली-**110011**

14. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे उल्लिखित समय सीमा के अंदर विहित स्वरूप और ढंग से जांच से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी अन्य पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तुत करना भी अपेक्षित होगा।

समय-सीमा

15. वर्तमान जांच से संबंधित सूचना को लिखित रूप में प्रेषित किया जाना चाहिए जिससे कि यह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से **40** दिनों (चालीस दिनों) से अतधिक समय में पहुँच जाए। यदि निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

16. वर्तमान मामले में सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना दें तथा अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करें और घरेलू उद्योग के आवेदनपत्र पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों के अंदर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। यह सूचना हार्ड कापी और साफ्ट कापी दोनों रूपों में प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

17 को करने वाले पक्षों से इसे दो (अनुबंध सहित /इससे संबद्ध परिशिष्ट)तिर सहित प्राधिकारी के समक्ष किसी प्रस्तुत्तर प्रत्युत्तप्रश्नो . पृथक सेटों में यदि "गोपनीयता" का इसके किसी भाग पर दावा किया जाता है फाइल किया जाना अपेक्षित है:-

(आदि सहित ,अनुक्रमणिका , की संख्यापृष्ठों ,शीर्षक) एक सेट गोपनीय रूप में (क) चिन्हित किया गया है, और

अनुक्रम , की संख्यापृष्ठों ,शीर्षक) सेट अगोपनीय के रूप में एक अन्य (ख)णिका चिन्हित किया गया है। (आदि सहित ,

18 . "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय " की प्रस्तुति प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय " रूप में स्पष्टचिन्हित की : ति प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय रूप में के बिना की गई प्रस्तुतजानी चाहिए । ऐसे चिन्होंसमझी जाएंगी और प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि ऐसी प्रस्तुति को जांचने के लिए वह अन्य इच्छुक पक्षों को अनुमत करे । दोनों संस्करणों की सॉफ्ट कापी भी प्रत्येक के पांच)5त किया जाना अपेक्षित होगा ।सेटों में हार्ड कापी के साथ प्रस्तु (

19. गोपनीय संस्करण ऐसी सभी सूचना समाविष्ट किए होंगे जो प्रकृति में गोपनीय हो और/अथवा अन्य सूचना जिसकी ऐसी सूचना की आपूर्ति करने वाला गोपनीयता के रूप में दावा करता हो। सूचना जिसका प्रकृति में गोपनीयता के रूप में दावा किया जाता है अथवा सूचना जिस पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है के लिए, सूचना आपूर्तिकर्ता से आपूरित सूचना कि ऐसी सूचना क्यों प्रकट नहीं की जा सकती है के साथ एक उचित कारक विवरण दिया जाना अपेक्षित है।

20. अगोपनीय संस्करण सूचना अनुक्रमित अथवा रिक्त किए गए (यदि अनुक्रमणिका सम्भव न हो) और जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया हो के आधार पर सार रूप में की गई गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सार इतने विस्तृत रूप में हो कि उससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार की पर्याप्त समझ प्राप्त हो सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि अनुसार उसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि उसका सार प्रस्तुत करना संभव क्यों नहीं है।

21. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच करने के पश्चात गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीय के लिए किया गया अनुरोध वांछित नहीं है अथवा सूचना का प्रदाता उस सूचना को सार्वजनिक करने का या तो इच्छुक नहीं है या उसका सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में प्रकटीकरण करने को प्राधिकृत करना नहीं चाहता है तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अवहेलना कर सकते हैं।

22. सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता की दावे के संबंध में सद्कारण के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतिकरण को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

23. प्रदान कराई गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लिए जाने पर प्राधिकारी ऐसी सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किए बिना किसी भी पक्षकार को उस सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

24. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुरूप कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय पाठ युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

25. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार किसी सूचना की पहुंच तक मनाही करता है और युक्तिसंगत अवधि के अंदर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में भारी व्यवधान उत्पन्न करता है तो प्राधिकारी उनको उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को समुचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2014

(Sunset Review)

Subject: Sunset review of anti-dumping duty imposed on the imports of Plain Medium Density Fibre Board originating in or exported from China PR, Malaysia, Thailand and Sri Lanka.

No 15/28/2013-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the AD Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) initiated the original anti dumping investigation in respect of the imports of Plain Medium Density Fibre Board (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from China PR, Malaysia, Thailand and Sri Lanka and definitive anti dumping duty was recommended vide Final Findings Notification No. 14/12/2007-DGAD dated 26th August, 2009. Accordingly, definitive anti dumping duties were imposed vide Ministry of Finance Notification No 116 / 2009-Customs dated the 8th October, 2009 on all imports of the subject goods originating in or exported from China PR, Malaysia, Thailand and Sri Lanka (hereinafter referred to as the subject countries).

Request for Review

2. Whereas, in terms of the Customs Tariff Act, 1995, the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition.

3. And, notwithstanding the above provision, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantial request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. And, whereas, in terms of the above provisions, Greenply Industries Limited and Mangalam Timber Products Limited, major manufacturers of Plain Medium Density Fibre Board in India, have approached the Authority with a

duly substantiated application requesting for sunset review of the anti-dumping duties earlier imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries vide Ministry of Finance Notification No 116 / 2009-Customs dated the 8th October, 2009 and seeking the continuation of anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries. The request is based on the grounds that dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries has continued in spite of the imposition of anti-dumping duties on the import of the subject goods from the subject countries and the domestic industry continues to suffer injury on account of dumping from the subject countries. The applicant has further argued that the expiry of the measure against the subject countries would be likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

5. And, the Authority on the basis of prime facie evidence given by the applicants considers that initiation of sunset review proceedings for the anti-dumping duties in force would be appropriate to examine the need for continuation of such duties to offset dumping from the subject countries and to examine as to whether the injury to the domestic industry is likely to continue or recur if the duties were removed or varied.

Domestic Industry and Standing

6. The application has been filed by Greenply Industries Limited and Mangalam Timber Products Limited (hereinafter referred to as the domestic industry or the applicants), major producers of Plain Medium Density Fibre Board. The applicants have listed other companies that are holding capacities to manufacture Plain Medium Density Fibre Board, viz., Rushil Décor Limited, Shirdi Industries Limited, Balaji Action Buildwell and Nuchem Limited and further stated that Nuchem Limited and another company, namely, Bajaj Eco-Tec Products Limited are no longer producing the product concerned. As per the information available on record, the applicants not only have major proportion of the total domestic production and thus constitute the domestic industry but also satisfy the requirement of standing to file the present sunset review application within the meaning of the Rules.

Initiation

7. Having satisfied itself on the basis of the positive prima facie evidence submitted by the domestic industry substantiating the need for a review, the Authority hereby initiates a Sunset Review in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of Antidumping Rules, to review the need for continued imposition of duties in force and whether the expiry of the duties would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

Product under Consideration and Like Article

8. The product under consideration in the present review investigation is Plain Medium Density Fibre Board having thickness of 6mm or more (hereinafter referred to as the product under consideration).

9. In the previous investigation conducted on the subject goods, the Authority had defined the product under consideration and its scope as under:

“6. The product under consideration is Plain Medium Density Fibre Board also known as Plain MDF Board in market parlance. Plain Medium Density Fibre Board, or Plain MDF Board is a composite wood product made out of wood waste fibres glued together with urea formaldehyde resin or melamine resin, heat and pressure. It is widely used for partitions, Modular furniture, cabinets etc. due to its smooth and uniform finish. MDF Board is produced in plain form and lamination is additional processing which is done after production of Plain MDF Board. The laminated Medium Density fibre Board (laminated MDF Board) is beyond the scope of product under consideration. The Authority in its Preliminary Findings considered the submissions received on the product under consideration and after due examination excluded the Plain Medium Density Fibre Board below 6MM thickness from the product scope and accordingly the product under consideration was considered as Plain Medium Density Fibre Board from 6MM thickness and above and same is also considered in this investigations.

7. The product is classified under heading 44.11 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975). The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.”

10. The scope of the product under consideration in the investigation shall remain the same as the scope of the product under consideration in the final findings earlier notified.

11. Further, the applicants submitted that the product manufactured by the domestic industry and the subject goods imported into India from the subject countries are like articles within the meaning of the Anti-dumping Rules; that there is no known difference between the subject goods imported from the subject countries and that produced by the domestic industry; that the subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods; that the consumers can use and are using the two interchangeably and that the two are technically and commercially substitutable. After examination, the Authority concludes that the subject goods produced by the domestic industry are like article to that imported from the subject countries.

Procedure

12. The investigation will determine as to whether the expiry of the measures would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority will examine as to whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duties were removed or varied.

- i. The review will cover all aspects of the Notification No. 116/2009-Customs dated the 8th October, 2009.
- ii. The countries involved in this review investigation are China PR, Malaysia, Thailand and Sri Lanka.
- iii. The period of investigation (POI) for the purpose of the present review is from October 2012 to September 2013 and for the injury analysis, data of the previous three years, viz., 2010-11, 2011-12, 2012-13 and the POI will be considered.
- iv. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rules shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

13. The exporters in the subject countries, their governments through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority

Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties

Ministry of Commerce and Industry

Department of Commerce

Room No 240, Udyog Bhavan, New Delhi-110011

14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

15. Any information relating to the present review should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

16. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

Submission of information on confidential basis

17. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:-

(a) one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and

(b) the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

18. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in five (5) sets of each.

19. The confidential version shall contain all information which are by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information can not be disclosed.

20. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

21. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the

information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

22. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

23. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

24. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

25. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. S. DEEPAK, Designated Authority